संख्या- 42 /2022/14-भा०स०/12-5-2022-सा0-01/2019

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ :: दिनांक: 30 जून, 2022**

विषयः-**प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत किसानों के भूलेख का विवरण पी0एम0किसान पोर्टल पर दर्ज करने के संबंध में।**

महोदय,

आप अवगत है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभार्थी कृषकों को रू.2000/- की तीन समान किश्तों में रू.6000/- प्रति वर्ष प्रदत्त किए जाने का प्राविधान है। प्रदेश में अब तक 2.59 करोड़ किसानों को रू.47397/- करोड़ की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।

2- उक्त योजना की परिचालित गाइडलाइन्स के अनुसार मृतक भूमिधर की वरासत के आधार पर नए भूमिधर किसानों के सिवाय 01.02.2019 से पूर्व के भूमिधर किसान ही योजना के पात्र है। इसके अतिरिक्त उक्त गाइडलाइन्स में उच्चतम आय की श्रेणी के किसान भी योजना की पात्रता से बाहर रखे गए हैं।

3- पात्र किसानों को योजना का लाभ पहुँचाने के उददेश्य से विभिन्न स्तरों पर पात्रता के मानक के अनुसार कार्यवाही करने हेतु विभिन्न उपाय यथा-आधार प्रमाणीकरण, पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर लाभार्थियों के खातो का प्रमाणीकरण, आयकर विभाग के सर्वर से आयकरदाताओं की पहचान तथा केन्द्र सरकार के कर्मियों एवं पेंशनर्स की पहचान आदि अपनाएं गए है।

4- पात्र किसानों की पहचान, उसका सत्यापन तथा लाभार्थी कृषकों की सूची का निरन्तर सुधार किया जाना अत्यावश्यक है। इस हेतु सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के संलग्न पत्र दिनांक 14.06.2022 द्वारा नए पात्र कृषकों की पहचान कर उनका पी0एम0किसान पोर्टल पर पंजीकरण कराने, अपात्र किसानों को चिन्हित कर उन्हे डिलीट करने एवं ई0के0वाई0सी0 कार्य पूर्ण करने तथा भूमि के विवरण सत्यापित करने के निर्देश दिये गये है। पी0एम0 किसान के लाभार्थियों के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार त्रुटिरहित विवरण अंकित करने से फार्मर डाटाबेस भी तैयार हो जाएगा, जिसका उपयोग भविष्य के अन्य योजनाओं में भी किया जा सकेगा। इसके साथ यह भी निर्देश दिये गये है कि दिनांक 31 जुलाई 2022 तक प्रत्येक लाभार्थी कृषक की भूमि का सत्यापन आवश्यक रूप से पी0एम0किसान पोर्टल पर कर लिया जाए।

5- केन्द्र सरकार द्वारा इस कार्य हेतु पी0एम0 किसान का डाटा डाउनलोड करने तथा राजस्व विभाग द्वारा लाभार्थी की भूमि सम्बंधी सूचना एक्सेल शीट पर अपलोड कर पी0एम0 किसान पोर्टल पर अपलोड करने हेतु स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर निर्गत किए हैं, जो पत्र के साथ संलग्न है।

6- तत्क्रम में जिला स्तर पर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए:-

6.1- जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक राजस्व ग्रामवार संलग्न प्रारूप पर समस्त लाभार्थियों का विवरण पोर्टल से निकाल कर सम्बन्धित तहसील को हार्ड कापी में हस्तगत करेंगे। इस हेतु आवश्यक स्टेशनरी व अन्य व्यय पी0एम0 किसान के प्रशासनिक मद से उपलब्ध कराया जाएगा। व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु पर्याप्त धनराशि जनपदों को कृषि निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

6.2- राजस्व कर्मी अपने-अपने सम्बन्धित राजस्व ग्राम में उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार लाभार्थी का विवरण एक्सेल शीट पर दर्ज करेंगे। इस कार्य का पर्यवेक्षण तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी द्वारा करते हुए समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

6.3- राजस्व कर्मियों से प्राप्त सूचना को एक्सल शीट पर निर्धारित प्रारूप में भरने के पश्चात् उसे तहसील लाग इन से अपलोड कर दिया जायेगा।

6.4- इस सत्यापन कार्यवाही के दौरान मृतक कृषक अथवा भूमिहीन/अन्य कारणों से अपात्र पाये गये लाभार्थी का भी चिन्हीकरण होने पर पृथक से इंगित किया जायेगा। ऐसे लाभार्थी के भविष्य के किस्त को रोकते हुए पूर्व किस्तों की वसूली भी की जायेगी।

6.5- इस कार्यवाही हेतु आवश्यक तहसील लाग इन संचालित करने हेतु आवश्यक सूचना जिलाधिकारियों द्वारा अविलम्ब निदेशक, कृषि को उपलब्ध करा दी जाय।

7- उक्त कार्य को पूरी सावधानी एवं त्रुटिरहित तरीके से कराने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कराते हुए सघन अनुश्रवण भी सुनिश्चित करें।

भवदीय,
दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मत्रांलय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके उपर्युक्त उल्लिखित पत्र दिनांक 14.06.2022 के संदर्भ में।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- समस्त संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डा० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

ई०-14770 (0)/12-2022

MANOJ AHUJA
SECRETARY

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
Government of India
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Department of Agriculture, Cooperation
& Farmers Welfare

Dated 14th June, 2022

Dear Chief Secretary,

As you are aware, Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) Scheme is a central sector scheme launched on 24th February 2019 with the objective to supplement the financial needs of land holding farmers. Till now financial assistance of more than Rs. 2 lakhs crores have been transferred to more than 11.35 crore farmer families.

2. As per operational guidelines of the scheme, a farmer is eligible for the benefits under the scheme, provided he/she owns land as per the record of right (RoR) maintained by the State Government and that he/she had acquired such right before 01.02.2019, except for cases of inheritance due to death. Farmers falling under certain exclusion criteria of higher income status are not eligible to avail benefits under the scheme (**Annexure-1**).

3. Additional Checks and balances are in place to validate the data of the registered farmers in terms of eligibility and exclusion criteria. Details of such validations are given at **Annexure-2**. It may please be noted that the following validations of beneficiaries are already being carried out centrally on the PM KISAN portal.

a) Aadhar authentication of beneficiaries through UIDAI Server.
b) Validation of bank accounts of the beneficiaries, through PFMS portal.
c) Validation of Income tax payee status of beneficiaries through Income Tax Server.
d) Validation of Central Government employees and pensioners through PFMS portal.

U.S. 16.6.22

4. The responsibility of identification and proper verification of the beneficiaries, however, lies with the State/UT Government. As and when the correct data of verified beneficiaries are uploaded on the PM-KISAN portal by respective State/UT Government, the financial benefits are transferred directly into the bank account of beneficiaries. Therefore, the list of beneficiaries under the scheme needs to be updated regularly by the States/UTs to ensure full saturation under the scheme and to remove ineligible beneficiaries, if any. A few instances, as mentioned below, have come to the notice of this Department:

Contd....2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

a) There could still be eligible beneficiaries who are left out from the ambit of the scheme. It may please be noted that a Self- Registration Mechanism has been made available through mobile app, PM KISAN portal and walk-ins via Common Service Centres. It is observed that many applications are pending with States for verification. These applications, therefore, need to be closed after proper field verification. States may also take up special drives to identify and register left out beneficiaries. (**Annexure-3**)

b) There may be ineligible beneficiaries who have been included under the scheme by the State/UT. These are largely due to lack of proper verification of the registered farmers in terms of their land details, Aadhar details, death cases and the exclusion criteria related to State Government employees and pensioners.

5. As ownership of cultivable land is the basic criteria for eligibility under the scheme, the land details of all the eligible beneficiaries, as per the operational guidelines are to be entered in the PM KISAN portal after due verification by the designated authorities of the State/UT. The State/UT Governments are to maintain the land records data with them in their systems, either manual or computerised.

6. A letter dated 24th September 2020 was issued to all states/UTs mentioning that if agreed by the State/UT, the land record details available with them can be integrated with PM-KISAN portal. However, only few states made progress in this direction. States/UTs were once again requested to get their land record API integrated with PM-KISAN vide letter dated 9th July, 2021.

7. Given the above circumstances, it has been decided that the States/UTs would carry out verification of details of all the beneficiaries, as specified below. The verification needs to be completed by 31st July 2022.

a. The States/UTs should mandatorily enter the land details of the beneficiaries in the PM KISAN portal. The land details so entered will be exactly as per the land record system of the State/UT. The land records in possession of the beneficiary should also be taken into consideration during the verification. Further, State/UT must put in place appropriate systems to avoid any arbitrary deletion of existing eligible beneficiaries. In case of any doubt, the State/UT may seek clarification from Government of India, before proceeding further.
b. In case of death of a beneficiary, the name should be removed or replaced with the next of kin, if otherwise eligible.

Contd…3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

c. E-KYC of all the eligible beneficiaries needs to be completed. A publicity campaign may be carried out by the States/UTs to ensure all the left out farmers do their E-KYC, by 31st July 2022.

d. States/UTs should use the details of State/UT Government employees & pensioners, as maintained in their Government database, and match with the beneficiaries in PM KISAN Portal.

e. The Agriculture Departments of States/UTs would work with the land records department of their respective State/UT and share two APIs with the Ministry for integrating the digitally maintained land records of the farmers with PM-KISAN portal.

8. As a long term measure, it is necessary to integrate PM KISAN portal with the digitally maintained land records of States/UTs. This will help the State/UT to easily carry out verification of beneficiaries, at any given point of time. The details of the proposed process for this exercise, which needs to be completed by 15th December, 2022, are given at **Annexure-4**. In order to initiate and coordinate next steps for this activity, it is important that the details of the two Nodal Officers from State/UT are shared at the earliest with Shri Rajeev Chawla, Chief Knowledge Officer and Advisor, DA&FW (email ID: rajeev.chawla@gov.in), who will be handholding the States/UTs in linking the digitally maintained land records with PM KISAN beneficiaries.

9. It may please be noted that the 12th instalment release to the farmers of the State/UT will depend on successful completion of the activities mentioned by the respective State/UT at para-7, by 31st July 2022.

10. Similarly, 13th instalment release will depend on successful completion of activities mentioned at Annexure-4, by 15th December 2022.

Anticipating your generous cooperation in facilitating PM KISAN, one of the largest DBT schemes in the world, reach out to every eligible farmer in the country.

With regards.

Yours sincerely,

(Manoj Ahuja)

Encl: As above

The Chief Secretary
(All States)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Annexure-1

Categories of persons excluded
from availing the benefits under PM KISAN scheme

i. All Institutional Land holders.
ii. Former and present holders of constitutional posts.
iii. Former and present Ministers/ State Ministers, Former/present Members of Lok Sabha/ Rajya Sabha/ State Legislative Assemblies/ State Legislative Councils,
iv. All superannuated/retired pensioners whose monthly pension is Rs.10,000/-or more.
v. All serving or retired employee of the Center/ State Govt or PSEs (Excluding Multi-Tasking Staff / Class IV/Group D employees) of above category
vi. All Persons who paid Income Tax in last assessment year
vii. Professionals like Doctors, Engineers, Lawyers, Chartered Accountants, and Architects etc. registered with Professional bodies
viii. NRIs, in terms of provisions of Income Tax Act, 1961

******

Annexure-2

Validations of Registered Farmers on PM-KISAN Portal

a. Mandatory data fields as well as data syntax are checked on PM-KISAN portal as first level validation.

b. Connectivity with PFMS server established to validate the bank accounts of the beneficiaries.

c. Integration with UIDAI Server: Data of registered farmers is sent for demographic validation using Aadhaar. In case of error, data is again opened to the States/ UTs for correction. After the corrections, it again goes for validation using Aadhar.

d. PM-KISAN system is integrated with Income Tax Server for sharing information of beneficiaries related to payment of income tax.

e. Connectivity with Central Governments pensioners data: PFMS provides Central Government pensioners data, which is matched with the list of farmers verified by State/UT.

f. Payment is processed through Sponsor banks and NPCI. From 11th instalment, payment is being made to the Bank account linked to beneficiary's Aadhar.

*****

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Annexure-3

Special drive to identify and register any left out beneficiary

The State/UT will ensure identification and saturation of the scheme with any left out eligible farmers. The suggested process for addition of eligible, but left out farmers, may be as follows:

1. Publicity about the scheme: While most of the farmers are aware about the schemes, the State/UT Government should give enough publicity about the program by taking special drive/campaign.

2. Drive at Gram Panchayat Level: The Agriculture Department at the State/UT level should work with the Panchayati Raj/ Rural Development Dept to take up a drive at the GP/Village level for saturation of the scheme with the eligible farmers. Village skits, dramas and door to door campaign should be taken up so that all eligible farmers are included into PM-KISAN.

3. Generating Unique list of farmers and then finding out who are left out: As per the PM-KISAN eligibility condition, any person whose name is found in Record of Right (RoR) owning agricultural property is eligible for PM KISAN benefit, subject to certain exclusion criteria. As the RoRs are digitized in many of the states, it should hence be possible to generate complete and unique list of farmers for each village and then verifying their eligibility.

****

Annexure-I

Process for linking digitally maintained land records with the PM KISAN Portal

1) The administrative department dealing with PM KISAN scheme will share the details of
   a. A **Nodal Officer** from the administrative department
   b. A suitable **Technical Nodal Officer** (from the **Revenue/Land Records Department**), not below the rank of a Joint Director.

2) The **details of the two Nodal Officers** will be shared with Shri Rajeev Chawla, Chief Knowledge Officer and Adviser, DA&FW (email ID: rajeev.chawla@gov.in), who will be handholding the States/UTs in linking of the digitally maintained land records with PM KISAN beneficiaries.

3) Wherever the land record details are not available in the PM-KISAN portal for a particular beneficiary, the State Government would immediately **enter** that information into the portal. The land details so entered will be exactly as per the land record system of the State/UT. This exercise is to be completed by 31st July 2022.

4) The Agriculture Departments of States/UTs would work with the land records department of their respective State/UT and get two APIs for integrating the digitally maintained land records of the farmers with PM KISAN portal.

5) These **two APIS** – one which takes ***Khasra*** number or Survey number as **input** and the second that takes ***Khata number / Khatauni*** number as input would be provided by State Government to the Ministry of Agriculture by 31st July 2022.

6) The Ministry would then provide a report to the State/UT comparing the PM KISAN beneficiary name with land owner name. The State/UT would go through the report and either confirm correct linkage or enter the correct land which belongs to the beneficiary. This exercise has to be completed by 15th December 2022.

7) Generation of the unique list of farmers and then finding out who are left out. As the RoRs are digitized in many of the states, it should hence be possible to generate complete and unique list of farmers for each village and then verifying their eligibility. This shall have to be completed by 15th December 2022.

****

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

PROCESS FLOW FOR

PM-KISAN BULK DOWNLOAD STEPS FOR STATES

Download Procedure Steps:

1. The user must log in on the PM-KISAN portal using the portal URL: https://fw.pmkisan.gov.in/ and navigate to the login page using the steps mentioned in the below images and enter the credentials shared to log in on the portal

Figure 1: The user must click on the Login Tab, and they will be redirected to the Login page, where they must enter the credentials provided to them to log in to the PM-KISAN portal

2. After successfully logging in to the portal, the user must navigate to the Download page using the following sequence → Go to the Download section in the Main Menu → Click on the Village Wise Land Details, then the user will be redirected to the Download Page.

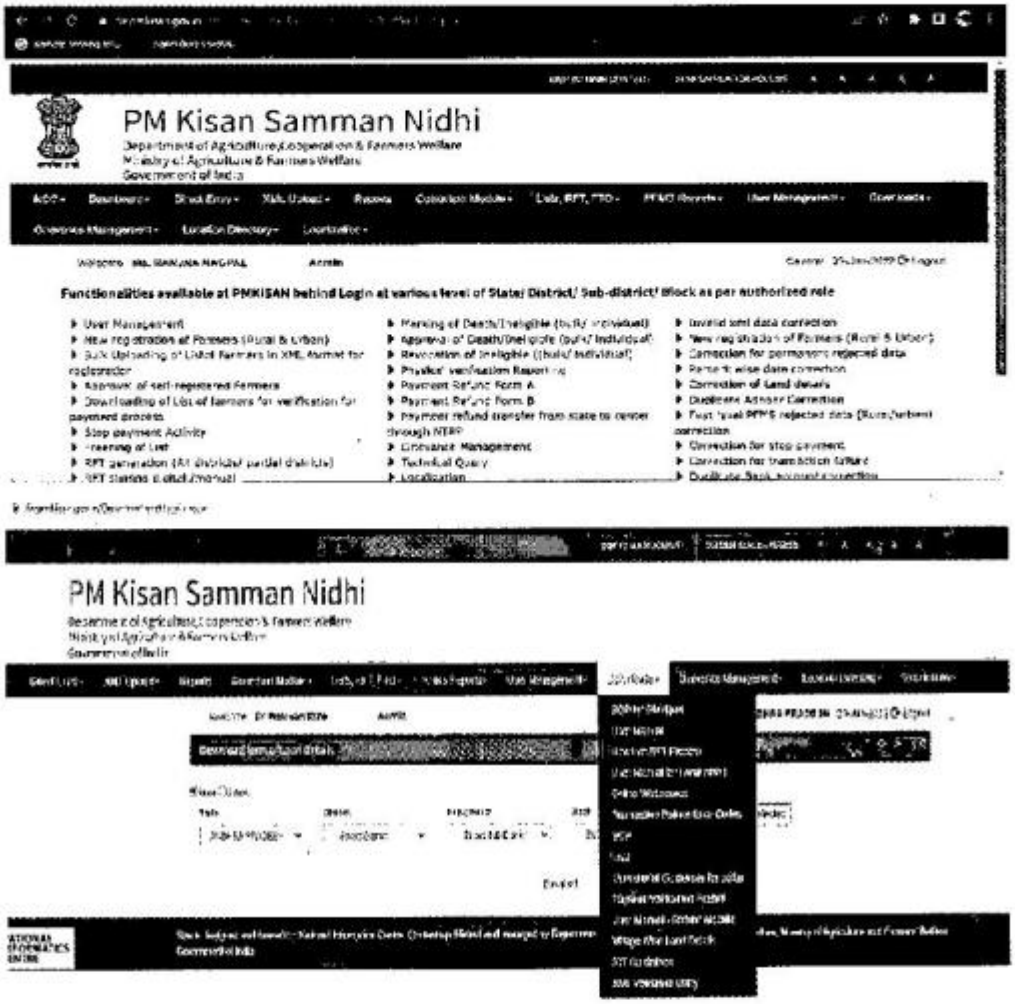
PM Kisan Samman Nidhi
Department of Agriculture,Cooperation & Farmers Welfare
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Government of India
Functionalities available at PMKISAN behind Login at various level of State/ District/ Sub-district/ Block as per authorized role
PM Kisan Samman Nidhi

Figure 2: Navigation to the Download Section, click on the Village Wise Land Details tab to arrive at the download page

3. On the download page, based on the user's role, the state and district will be pre-populated on the download page. The download button will only be activated after the user selects the sub-district from the drop-down; then, further user may choose a block to download the village-wise data

Figure 3: The download page available to the states

The excel file download format and the fields which are to be populated are described below on the next page. The states are advised that all the data they have to be maintained in the downloaded excel file; there won't be any field-wise upload; the excel file will have to be uploaded as it is after the data is populated. The upload module will be provided to the states at a later stage.

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रारूप

क्र.सं.	राज्य का एल.जी.डी. कोड	जनपद का एल.जी.डी. कोड	तहसील का एल.जी.डी. कोड	गॉव का एल.जी.डी. कोड	भूमि का खतौनी संख्या	किसान का खसरा संख्या	भूमि स्थानान्तरण का दिनांक	कृषक का नाम	कृषक के पिता का नाम	भूमि स्थानान्तरण का प्रकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12